

16

नवीन शिक्षा प्रणाली २०२० के अन्तर्गत सम्मिलित स्कूल शिक्षा प्रणाली ५+३+३+४ का विश्लेषणात्मक अध्ययन

जयेश सौरभ ठोपने
(शोधार्थी)

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अंबिकापुर
सरगुजा (छ. ग.)

डॉ शम्पु तिर्की
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)
रा. गाँ. शासकीय स्नातकोत्तर, महाविद्यालय
अंबिकापुर (छ. ग.)

संक्षेपिका :

२९ जुलाई २०२० को घोषित की गई नई शिक्षा नीति — २०२०, भारत सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल है, जिसके अन्तर्गत मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाए जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिससे यह सरल तो होगा ही क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण भी होगा। आयु वर्ग के आधार पर शिक्षा का वर्गीकरण भी शिक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। इसी परिकल्पना के साथ मैंने इस शोध पत्र को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

प्रस्तावना एवं विश्लेषण

शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य के ज्ञान का शीघ्र प्रसार होता है। समय— समय पर शिक्षा से जुड़ी नीतियों में बदलाव की आवश्यकता महसूस होती है और पुरानी शिक्षा नीति का स्थान

डॉ. विनोद खन्ना (प्राचार्य) शासकीय महाविद्यालय, पीथमपुर, जिला— धार (म.प्र.)

नयी शिक्षा नीति ग्रहण करती है और इसी तारतम्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६ के स्थान पर केन्द्रीय कैविनेट द्वारा नयी शिक्षा नीति २०२० पारित किया गया। नयी शिक्षा नीति में १०+२ के स्थान पर ५+३+३+४ का प्रावधान किया गया है।

पुरानी शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम १०+२ के आधार पर निर्धारित था किन्तु नयी शिक्षा नीति २०२० में शैक्षणिक संरचना ५+३+३+४ के आधार पर की गयी जिसमें बच्चे ३ से ८, ८ से ११, ११ से १४ व १४—१८ वर्ष की आयु के आधार पर ४ अलग — अलग समूह में विभाजित होंगे।

प्रथम — (५) फाउंडेशन स्टेज —

यह प्रथम स्टेज है, फाउंडेशन स्टेज के अन्तर्गत प्रथम तीन वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी / नर्सरी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेना होगा। इसके बाद बच्चे अगले दो वर्ष कक्षा पहली एवं दूसरी का अध्ययन करेंगे। इसमें ३ वर्ष से लेकर ८ वर्ष की आयु के बच्चों को लिया जाएगा। इस प्रकार प्रथम ५ वर्ष का पहला चरण पूर्ण होगा।

द्वितीय — (३) (प्रोप्रेटरी स्टेज) —

५+३+३+४ के द्वितीय चरण ३ वर्ष के अन्तर्गत कक्षा ३ से ५ तक की पढ़ाई होगी इसमें ८ से ११ वर्ष की आयु के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। इस चरण में बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई करायी जाएगी। इस प्रकार इस चरण के ३ वर्ष पूरे होंगे।

तृतीय — (३) (मिडिल स्टेज) —

कक्षा ६ से लेकर ८ तक की पढ़ाई को मिडिल स्टेज के अन्तर्गत रखा गया है। इस स्टेज में ८ से ११ वर्ष की आयु तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी द्य नयी शिक्षा नीति २०२० की विशेष बात यह है कि बच्चों में कौशल विकास को इसी स्टेज में रखा गया है, कौशल विकास के कोर्स कक्षा छठवीं से ही शुरू किये जाएंगे।

चतुर्थ — (४) सेकेण्डरी स्टेज —

५+३+३+४ के अंतिम चरण ४ के अन्तर्गत

सेकेण्डरी स्टेज को रखा गया है। जिसमें कक्षा ९ से लेकर १२ वीं तक की पढाई होगी। सेकेण्डरी स्टेज के लिए १४ से लेकर १८ वर्ष तक के उम्र के बच्चों को समिलित किया जाएगा। इस चरण में बच्चों को अपने विषय के चयन की स्वतंत्रता होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६ में विषय चयन की स्वतंत्रता बच्चों को कक्षा ११ वीं से मिलती थी।

निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति (NEP—२०२०) ३४ वर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगा जो सत्र १९८६ में लागू की गयी थी। इसरो पूर्व प्रमुख के कस्तुरीरामन ने कुशलतापूर्वक उस समिति का नेतृत्व किया जिसने नई शिक्षा नीति २०२० विकसित की है। वर्तमान परिवेश के आधार पर NEP—२०२० में स्कूलों के लिए निम्न दिशानिर्देश जारी किये गये हैं—

(१) NEP—२०२० के आधार पर भारतीय और क्षेत्रीय भाषाओं की ओर पर्याप्त ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए और नई शिक्षा नीति के अनुसार संस्कृत भाषा को शिक्षा प्रणाली में मुख्य धारा में लाया जाएगा।

(२) पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र २१ वीं सदी के प्रमुख कौशल से लैस करके शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए लक्ष्य करेगा।

(३) इस शिक्षा नीति के तहत कक्षा ६ वीं से स्कूलों में बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा दी जाएगी जिसमें इंटर्नशिप शामिल होगी।

(४) स्कूली छात्रों को केवल कक्षा ३, ५, ८ के लिए परीक्षा में शामिल होना होगा वाकि कक्षाओं में मूल्यांकन एक 'नियमित और औपचारिक' शैलियों का पालन करेगा।

(५) NEP २०२० के तहत भारत की शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला, समग्र और बहु विषयक बनाना है जिससे देश एक वैश्विक ज्ञान केन्द्र बने।

(६) कौशलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धातु कार्य, वागवानी, मिट्टी के वर्तन बनाने, बढ़ाईगिरी,

विजली के काम और अन्य दैनिक उपयोगी कार्यों के लिए कक्षाएं लगाने का फैसला किया है। यह इस शिक्षा नीति में कौशल विकास हेतु व्यवसायिक शिक्षा को जोर देगा और NEP—२०२० का यह लक्ष्य है कि २०२५ तक न्यूनतम ५०% बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा हासिल हो सके।

निष्कर्ष :

NEP २०२० के फॉर्मूला ५+३+३+४ के तहत भारत की शिक्षा व्यवस्था को वर्तमान बदलते हुए परिवेश के आधार पर प्रासंगिक बनाया गया है। कर्नाटक ने नयी शिक्षा नीति २०२० लागू कर इस दिशा में बदलाव की पहल कर दी है निश्चित रूप से यह नई शिक्षा नीति भारत को पुनः अपने अतीत के गैरव—विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर करेगा।

सन्दर्भ :

१. नए भारत की नीव — इन्जी. अवनीश कुमार सिंह

२. नयी शिक्षा नीति २०२० और मेरे विचार — जितेन्द्र यादव

३. राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० एक सरल परिचय — डॉ एस पी गुप्ता — डॉ अलका गुप्ता

